

7.1.9 Sensitization of students and employees of the Institution to the constitutional obligations: values, rights, duties and responsibilities of citizens

# **Prayaas**

A social initiative of GLA University was started in 2014 with a motif to help school students and school teachers by conducting health awareness, motivational and educative activities.



# **National Service Scheme Cell**

The department of Education at GLA University actively conducts activities from time to time in order to spread social awareness about issues like Child Abuse, Illiteracy, Alcoholism, Corruption etc.

### 1 March, 2019



# **Social Awareness**

The department of Education at GLA University actively conducts activities from time to time in order to spread social awareness about issues like Child Abuse, Illiteracy, Alcoholism, Corruption etc.

### **25 February, 2019**



### <u>Udaan</u>

Our mission is to provide the basic education to the underprivileged section of the society, which will ensure that they will get equal opportunities for their growth. We also work in the areas of social awareness like Child Labour, Women Empowerment, Environmental Safety and Cleanliness.

### 12 June, 2018



### **Aashayein**

This social club is focusing on eradication of poverty and social injustice. Under the aegis of this club many activities are organized time to time like Education Camp, Distribution Campaign, children's day celebration, Tree Plantation Campaign, Anti-Polythene Campaign, festival celebration at old age home etc.

### 7 September, 2019



# <u>Ujjwal Braj</u>

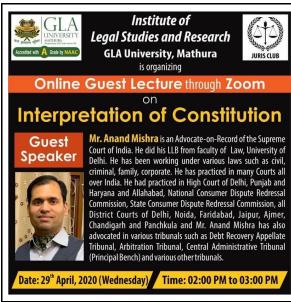
A group of students at GLA University that conducts cleaning activities in areas adjoining Goverdhan hill from time to time. A lot of work of beautification and cleanliness has been done by this lively group thus far.

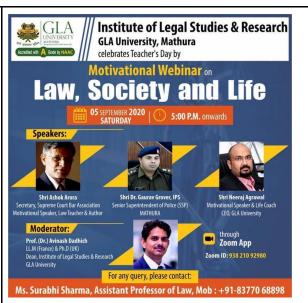
### 2 October, 2021



#### **Legal Aid Clinic**

The Institute of Legal Studies and Research has facility to provide free legal aid to the needy and who make requests for the same. The Institute of Legal Studies and Research also conducted various Webinars, online guest lectures, certificate courses to sensitize the students and employees of the Institution to the constitutional obligations.







कि पोस्को एक्ट में 10 प्रतिशत गलत केस सामने आते हैं, 90 प्रतिशत चार्ज सीट दर्ज होती है, जिनमें से 30 प्रतिशत अपराध सिद्ध होते हैं। 60 प्रतिशत मामलों में साक्ष्य न मिलने के कारण अपराधी को बरी कर दिया

सीबीआई के संयुक्त निदेशक डॉ. गोस्वामी जीएलए विश्वविद्यालय के ਕੀਸ਼ਕ ਸ਼ਟਵੀਤ ਸ਼ਕੂੰ ਸਿਸ਼ਦੀ ਰਿਖਾਸ਼ ਸ਼ੇ पॉक्सो एक्ट विषय पर जिला विधि सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर आयोजित वेबिनार में बोले रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत किए गए अपराधों पर सत्यता साबित करने के लिए डीएनए

साबत करने के लिए डीएनए सैम्प्रलिंग का डाटा तैयार होना चाहिए। वेबिनॉर में जिला न्याय सेवा प्राधिकरण, मधुरा की सचिव एवं न्यायाधीश दीक्षा श्री ने निशुल्क विधि सेवा दिए जाने की जानकारी दी और बताया कि किसी अपराध में दोषी को सजा की बात तो सब जानते हैं, लेकिन पीड़ित को मुआवजे की जानकारी बहुतों को नहीं होती। उन्होंने बताया कि जिला न्याय सेवा प्राधिकरण पॉक्सो एक्ट पीड़ित को मुआवजा दिलवाने में मदद करता है। सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्त

डॉ. चारू माथुर ने उक्त विषय पर कह कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च



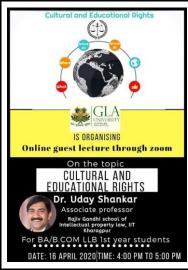
निदेशक व न्यायाधीश के साथ संस्थान के विधि संस्थान के हैड व अन्य।

न्यायालय इस विषय पर बेहद संवेदनशील है। साथ ही उन्होंने हर राज्य में इस एक्ट के अन्तर्गत फ्रस्ट टेउक कोर्ट एवं न्यायालयों को उचित संसाधन उपलब्ध कराने की भी बात की। जीएलए विधि संस्थान में सेंटर **फॉर** चाइल्ड राइटस रिसर्च और एडवोकेसी के हेड एवं इंडीपेडेंट थॉट के फउंडर विक्रम श्रीवास्तव ने पॉक्सो

एक्ट प्रावधानों पर प्रकाश डाला। वेबिनार के समापन पर विधि ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए

कहा कि भविष्य में पॉक्सो एक्ट विषय पर व्यापक चर्चा करने के लिए ऑनलाइन मंच पर विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस वेबिनार में 1300 से अधिक लोगों ने भाग लिया। जिसमें जीएलए विधि संस्थान के छात्र, शिक्षक न्यायाधीश, अधिवक्ता, पुलिस अधिकारी, समाज सेविकाएं आदि शामिल हुईं। कार्यक्रम की कोडिंनेटर विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर सुरभी शर्मा ने कार्यक्रम का सफ्ल संचालन कराया।





#### जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद न्यायालय मथुरा द्वारा ऑनलाइन वेबीनार जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015'' का कार्य सम्प्पन किया गया

**हिन्द वतन।** उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीय जनपद न्यावाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मधुरा के निदेशांनुसार इस्टिट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज एवं रिसर्च जीएलए विश्वविद्यालय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा के संयुक्त तत्वावधान में "जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015" विषय पर ऑनलाइन जागरुकता पोगाम (वेबीनार) संपन्न करवाव गया। इस अवसर पर उक्त विषय में देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने अपने दश के आजात विश्वास्त्र ने अपन विचार जान किए। मुद्रा जनपद की पुलिस अमीक्षम (हिन्दी एजरि) ग्रीति सिंह ने जुनेनाहर किल्पिस स्त्रा हिम्म एक्ट के तहत आने वाले केस में तौर पर जिल्ला विधिक सेवा विवेचना की प्रक्रिया को विस्तर प्राफिक्टण मुद्रा की सचिव दीआजी पूर्वक बताया, साथ ही जुवेनाइल जस्टिस एंड प्रोटक्शन एक्ट, कार्यप्रणाली व चिल्डुन कोर्ट के बारें के तौर पर स्टेट कमीशन फोर गया। चर्चा को आगे बढ़ातें 2015 के प्रावधानों पर प्रकाश में जानकारी दी, साथ ही जिला प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, नई दिर



ने ज्वेनाइल जस्टिस बोर्ड की

डाला गया। कार्यक्रम के अगले वक्ता

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में क्या कार्य करने वाले एनजीओ एवं अन्य भूमिका होती है, इस पर प्रकाश एजेंसी के साथ मिलकर कैसे कार्य करते हैं, इस बिंद पर प्रकाश डाल गया। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जवेनादन जस्टिस बोर्ड, नई दिल्ली

की सदस्य केसर प्रवीन के द्वारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की कार्य प्रक्रिया पर फोकस कर वास्तविक

उदाहरण दिए गए। कार्यक्रम के मॉडरेटर विक्रम श्रीवास्तव ने जुवेनाइल जस्टिस एवं प्रोटेक्शन एक्ट के विभिन्न आयामीं पर चर्चा की। अंत में इंस्टीट्यूट आफ लीगल स्टडीज एवं रिसर्च के निर्देशक प्रोफेसर अविनाश दाधीचि ने अपने लॉ स्कूल के बारे में बतावा कि हम लगातार इस जुवेनाइल एक्ट पर अपने छात्रों को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही इस विषय पर सेमिनार आयोजित करा 1000 लोगों द्वारा ऑनलाइन देखा गया।

हर एक का र



**Protection of Children from Sexual** Offences Act (POCSO)

31st July, 2020, 5:00 PM Onwards **SPEAKERS** 



Dr. G K Goswami, IPS Joint Director,

Smt. Diksha Shree Secretary, District Lega



Surabhi Sharma +91-8377068898

UNIVERSITY Accredited with A Grade by NAAC 12-B Status from UGC

nouaht endent Thought

Online

#CCCRL #1st Edition #Summer2021

Children Law Research Centre [CLRC] Institute of Legal Studies and Research, GLA University in Technical Collaboration with Independent Thought

organises

# Certificate Course on Child Rights Law

30 hrs. Weekend Course (Saturday & Sunday) Saturday - 6:00 PM to 8:00 PM Sunday - 11:00 AM to 1:00 PM

Eligibility: The course is open to all but especially designed for Students of Law, Criminology, Social Work, Researchers, Teachers and NGO Management who are interested in the field of Child Rights. Working professional who can immensely benefit are those in NGOs, Police, Lawyers, School Teachers and Counselors among others.

Registration Last Date: 31st March, 2021

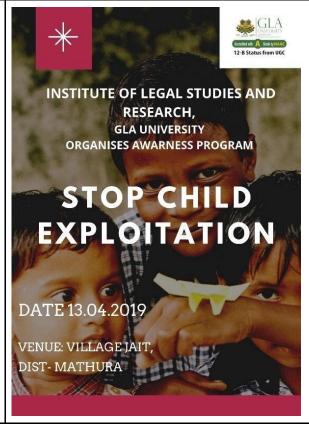
Registration Link- https://forms.gle/cnnLkPEegLHu3c6M7

Cost: INR 4000/for Indian Nationals and USD 75/for Foreign Nationals

**Lecture by Faculties Comprising of** Academics, Jurists, Lawyers and **Practitioners. Activists** 

Ms. Afsana Ahmed, Programme Coordinator (Law), Independent Thought Contact: +91- 9999899494 | Email: centreclrc@gla.ac.in





### **Gender Sensitization**

The university regularly organizes events, seminars and workshops to sensitize the staff and students on the concept gender.



AND RESEARCH,
GLA UNIVERSITY



GENDER SENSITIZATION THROUGH CHANGING THE NARRATIVES



SPEAKER - PRATISHTHA SINGH, LEGAL COUNSEL, AZB & cO.

DATE: 02.05.2021 TIME- 10A.M. IST



Zoom id - 88735778799 passcode - 227865



Students participating in Gender Equity Program

### **Women Security Program**









# **Sports Activities**

S.NO	GAME	EVENT NAME
1	ATHLETICS	PRATHAM PRATIBHA
2	BADMINTON	
3	BASKETBALL	HOOP IT UP
4	CHESS	
5	CRICKET	GCC
6	FOOTBALL	FUTSAL
7	NATIONAL SPORTS DAY	





















